Jaipur Municipal Corporation to Launch ‘Amrit Seva Abhiyan’ on Nirjala Ekadashi

On the occasion of Nirjala Ekadashi, the Amrit Seva Abhiyan will be launched in the city of Jaipur by the Jaipur Municipal Corporation. The purpose of the campaign is to help ease the public in times of extreme heat and to foster a sense of service, public welfare and civic responsibility. Keeping in mind the message of the chief minister, Bhajanlal Sharma, who encouraged people to take hands-on efforts to provide facilities to the citizens and serve the people, the idea was conceived to make Nirjala Ekadashi not just a religious festival but a festival of service, compassion and social responsibility among the people. This initiative will establish service camps in all parts of Jaipur through the effort of social bodies, businesses, voluntary organizations and citizens.

The key features of Amrit Seva Abhiyan are the following:

- The campaign will be organised by the Jaipur Municipal Corporation on 25th June.
- It is associated with Nirjala Ekadashi which is a day in which devotion and service is considered.
- Service camps will be set up in various places in Jaipur.
- There will be the availability of cool drinking water, sherbert, juice, buttermilk and fruit based drinks for passers-by and those in need.
- The campaign encourages citizens' involvement, voluntary service and social cooperation.

- It highlights the responsibilities of urban local bodies in times of extreme heat in terms of public welfare.

Objectives and Benefits

Objectives

- To relieve people from extreme heat during summer.
- To encourage citizens to be involved in the provision of services in urban areas.
- To link social institutions, trade organisations, voluntary groups and citizens to civic welfare.
- To build the culture of compassion, co-operation and social responsibility.

Benefits

- It will help needy people and pedestrians access basic heat-relief facilities.
- It will promote community based support to urban governance.
- It will increase the coordination between the municipal corporation and civil society.
- It will encourage the concept of festival as a time of public service.

Registration and Civic Support

Omprakash Kasera, Municipal Commissioner, said that the interested citizens, social organizations, business organizations and voluntary organizations can register online at www.amritseva.in. Another option for registration is to scan the QR code provided by the Municipal Corporation. The Municipal Corporation will arrange for the provision of necessary support like canopies, chairs, tables, fans, front branding banners and other cleanliness related support after allotment and registration is completed.

RAS Exam Relevance

The news is relevant to RAS exam as it relates to the issues of urban governance, public health, heat wave relief, local self-governance and citizens' participation. It is also an indicator of the role of religious/cultural events in public good and community mobilization by municipal bodies. The initiative underscores the importance and value of civic services offered by the urban local bodies and the development of a people-centric governance model.

Conclusion

The Amrit Seva Abhiyan is one of the vital instances of service-based urban governance. Faith, public welfare and citizen participation are the three key elements with which Jaipur Municipal Corporation wants to ensure relief in times of extreme heat and foster a culture of cooperation and social responsibility. These types of programs enhance citizens' trust in civil society and local government institutions.

RASonly

MCQs

MCQ 1:In which local body, in an urban area, is the Amrit Seva Abhiyan being organised on Nirjala Ekadashi?

A. Jaipur Development Authority

B. Jaipur Municipal Corporation

C. Rajasthan Urban Infrastructure Development Project

D. Rajasthan Housing Board

Answer: B. Jaipur Municipal Corporation.

Explanation: In the honor of Nirjala Ekadashi, Jaipur Municipal Corporation will organize Amrit Seva Abhiyan. The campaign focuses on public service, heat relief and citizen participation.

MCQ 2:What is the main objective of the Amrit Seva Abhiyan?

A. To organise a tourism festival in Jaipur
B. To provide relief to people during summer heat through public service camps
C. To launch a new urban transport project
D. To conduct a city-wide tax collection drive

Answer: B. To provide relief to people during summer heat through public service camps

Explanation: The campaign aims to provide cool drinking water, sherbet, juice, buttermilk and fruit-based refreshments to pedestrians and needy people during intense summer heat.

MCQ 3: After registering and allotment, Jaipur Municipal Corporation will provide which of the following facilities?

A. Canopies, chairs, tables, fans and cleanliness-related support
B. Free electricity connections to all households
C. Permanent shops for traders
D. Free residential plots for voluntary organisations

Answer: A. Canopies, chairs, tables, fans and cleanliness-related support

Explanation: After registration and allotment, Jaipur Municipal Corporation will provide canopies, chairs, tables, fans, front branding banners and general cleanliness-related support for service camps.

RASonly

निर्जला एकादशी पर जयपुर नगर निगम चलाएगा ‘अमृत सेवा अभियान’

निर्जला एकादशी के अवसर पर जयपुर नगर निगम द्वारा शहर में ‘अमृत सेवा अभियान’ शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना तथा सेवा, जनकल्याण और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नागरिक सुविधाओं और जनसेवा को प्राथमिकता देने के संदेश को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य निर्जला एकादशी को केवल धार्मिक पर्व तक सीमित न रखकर सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व के उत्सव के रूप में स्थापित करना है। इस पहल के अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों के सहयोग से जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा शिविर स्थापित किए जाएंगे।

अमृत सेवा अभियान की प्रमुख विशेषताएं

- यह अभियान जयपुर नगर निगम द्वारा 25 जून को आयोजित किया जाएगा।
- यह अभियान निर्जला एकादशी से जुड़ा है, जिसे परंपरागत रूप से आस्था, सेवा और दान-पुण्य से संबंधित माना जाता है।
- जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाए जाएंगे।
- राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को शीतल पेयजल, शरबत, जूस, छाछ और फलाहार उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह अभियान नागरिक सहभागिता, स्वैच्छिक सेवा और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह पहल अत्यधिक गर्मी की स्थिति में जनकल्याण के लिए शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को रेखांकित करती है।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

- गर्मी के मौसम में लोगों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान करना।
- शहरी क्षेत्रों में सेवा वितरण में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों, स्वयंसेवी समूहों और नागरिकों को नागरिक कल्याण से जोड़ना।
- समाज में संवेदना, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व की संस्कृति को मजबूत करना।

RASonly

लाभ

- इससे जरूरतमंद लोगों और राहगीरों को गर्मी से राहत देने वाली आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी।
- यह शहरी शासन में समुदाय आधारित सहयोग को बढ़ावा देगा।
- इससे नगर निगम और नागरिक समाज के बीच समन्वय मजबूत होगा।
- यह त्योहारों को जनसेवा के अवसर के रूप में देखने की अवधारणा को प्रोत्साहित करेगा।

पंजीकरण और नागरिक सहयोग

नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा ने बताया कि इच्छुक नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक प्रतिष्ठान और स्वयंसेवी संगठन www.amritseva.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा जारी QR कोड को स्कैन करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण और आवंटन के बाद नगर निगम द्वारा कैनोपी, कुर्सियां, टेबल, पंखे, फ्रंट ब्रांडिंग बैनर और सामान्य स्वच्छता से संबंधित आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

RAS परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यह समाचार RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहरी शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, हीटवेव राहत, स्थानीय स्वशासन और नागरिक सहभागिता जैसे विषयों से जुड़ा है। यह इस बात का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों का उपयोग जनकल्याण और सामुदायिक सहभागिता के लिए किस प्रकार किया जा सकता है। यह पहल शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं की उपलब्धता और जन-केंद्रित शासन मॉडल के विकास को भी रेखांकित करती है।

निष्कर्ष

अमृत सेवा अभियान सेवा आधारित शहरी शासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आस्था, जनकल्याण और नागरिक सहभागिता को जोड़ते हुए जयपुर नगर निगम भीषण गर्मी के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने और समाज में सहयोग, संवेदना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे कार्यक्रम नागरिक समाज और स्थानीय शासन संस्थाओं के प्रति विश्वास को भी सुदृढ़ करते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

MCQ 1

निर्जला एकादशी पर अमृत सेवा अभियान किस शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित किया जाएगा?

RASonly

A. जयपुर विकास प्राधिकरण

B. जयपुर नगर निगम

C. राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना

D. राजस्थान आवासन मंडल

उत्तर : B. जयपुर नगर निगम

व्याख्या : अमृत सेवा अभियान निर्जला एकादशी के अवसर पर जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह अभियान जनसेवा, गर्मी से राहत और नागरिक सहभागिता पर केंद्रित है।

MCQ 2

अमृत सेवा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. जयपुर में पर्यटन महोत्सव आयोजित करना

B. सार्वजनिक सेवा शिविरों के माध्यम से गर्मी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना

C. नया शहरी परिवहन प्रोजेक्ट शुरू करना

D. शहर में कर संग्रह अभियान चलाना

उत्तर: B. सार्वजनिक सेवा शिविरों के माध्यम से गर्मी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना

व्याख्या: इस अभियान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को शीतल पेयजल, शरबत, जूस, छाछ और फलाहार जैसी राहत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

MCQ 3

पंजीकरण और आवंटन के बाद जयपुर नगर निगम द्वारा कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

A. कैनोपी, कुर्सियां, टेबल, पंखे और स्वच्छता संबंधी सहयोग

B. सभी घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन

C. व्यापारियों को स्थायी दुकानें

D. स्वयंसेवी संगठनों को मुफ्त आवास

उत्तर: A. कैनोपी, कुर्सियां, टेबल, पंखे और स्वच्छता संबंधी सहयोग

व्याख्या: सेवा शिविरों के पंजीकरण और आवंटन के बाद जयपुर नगर निगम द्वारा कैनोपी, कुर्सियां, टेबल, पंखे, फ्रंट ब्रांडिंग बैनर और सामान्य स्वच्छता से संबंधित सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

RASonly

RASonly

Rajasthan to Extract Critical Minerals from Mineral Dumps

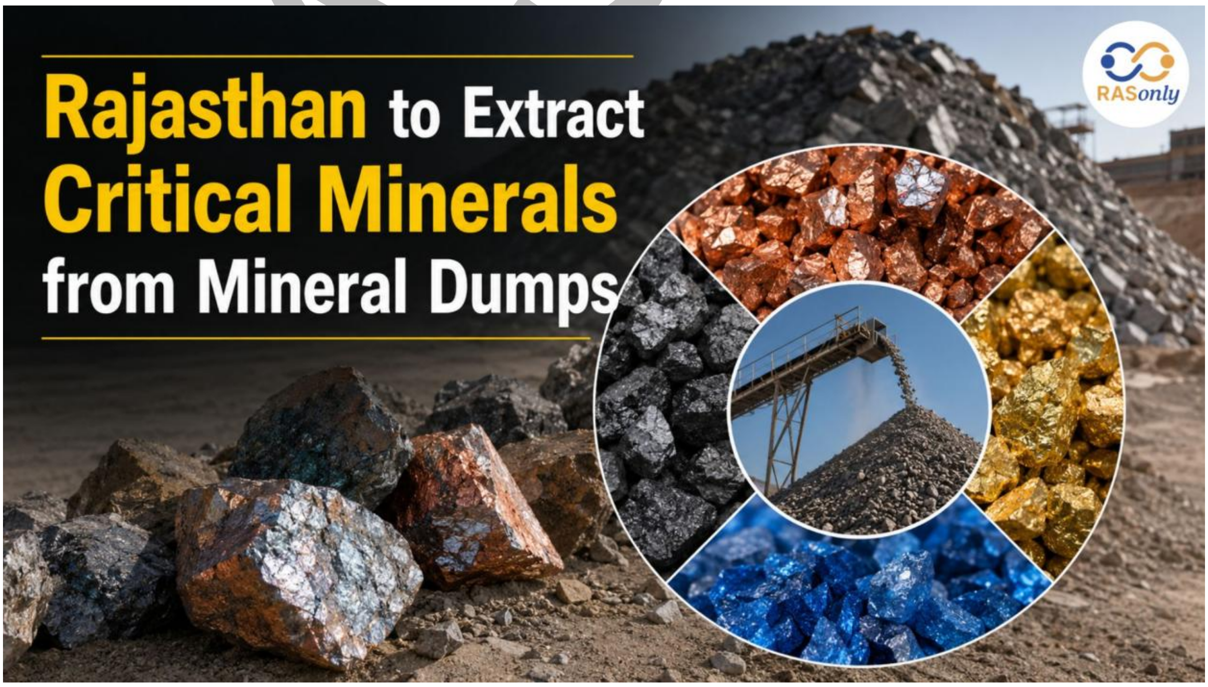

Rajasthan is taking a revolutionary step in the mining sector, looking into critical minerals from mineral waste dumps. Under the leadership of Chief Minister Bhajanlal Sharma and in

line with Prime Minister Narendra Modi's focus on critical and strategic minerals, the state has started scientific studies of mineral dumps to identify valuable resources. Some initial research from the field of pink marble and green marble waste in Rajasthan has revealed encouraging results for a quality amount of key minerals like nickel, cobalt, chromium and gallium. Defence, green energy, aerospace and aeronautical industries are important applications for these minerals. The initiative can enhance the energy security, strategic security and economic security of India.

The key features of the initiative are:

- Rajasthan is exploring minerals from the mineral dumps and mining waste which are not used.
- Positive indications of nickel, cobalt, chromium and gallium have been found in the study of pink marble and green marble waste.
- These minerals are useful in the fields of defence, renewable energy, aerospace and aeronautics.
- The initiative is associated with the National Critical Mineral Mission launched by Prime Minister Narendra Modi.
- Rajasthan State Mineral Exploration Trust and IIT Dhanbad have signed a pact for scientific study of the mineral dumps.
- The goal is to recover valuable critical and strategic minerals from waste streams to be used for commercial production.
- The agreement was signed between RSMET and IIT Dhanbad.

Institutional Partnership

The Department of Mines has signed an agreement with the IIT Dhanbad to study the mineral dumps in Rajasthan under Rajasthan State Mineral Exploration Trust. The deal is too concentrate on finding valuable critical and strategic minerals in these massive unexploited mineral dumps throughout the state.

Purpose of the Agreement

The main purpose of the agreement is to scientifically evaluate mineral waste, identify critical minerals and explore the possibility of commercial production. Here, the concept of circular mining is encouraged in which mining waste is used as a resource rather than a waste.

A pilot project and findings are provided

As per the agreement, 78 mineral dumps were identified in a pilot project by the Mines Department. These dumps were clustered into 10 dumps clusters. A total of 8 dumps of pink marble and 2 dumps of green marble (serpentinite) were studied in one cluster around the Udaipur district.

RASonly

Significant amounts of Ni, Co, Cr and Ga were detected in these dumps. Initial estimates suggest that their concentration might be 25 to 40 times greater than their normal abundance on the Earth's crust. This is important for future mineral resource planning and strategic mineral security purposes.

Further Scientific Evaluation

68 dumps and tailings remain are also being scientifically assessed with the help of IIT ISM Dhanbad. Evaluation consists of mapping, geo-referencing of databases, sampling, extraction, mineralological analysis and assessment of available resources.

The study will be conducted to look for the important minerals like tungsten, lithium, cobalt, nickel and the rare earth elements. Mineral dumps are already found in some other areas like Udaipur, Banswara, Dungarpur, Pratapgarh, Salumber, Rishabhdev, Ajmer, Beawar, Sawar, Nagaur, Sirohi, Jodhpur, Balesar, Sojat City and Jalore.

Link with National Critical Mineral Mission

National Importance

The National Critical Mineral Mission is responsible for exploration and mining activities of critical and strategic minerals, such as rare earth minerals, heavy rare earth minerals and critical rare metals. Rajasthan's initiative directly contributes to this mission by studying critical minerals from the existing mineral dumps.

Rajasthan's Role

Rajasthan has taken a unique initiative by having started the exploration of critical minerals from the mineral dumps. Progress has also been made in the rare earth mineral industry by the state. In recent years, the rare earth elements – critical and strategic – were discovered in the Siwana Ring Complex, while the Central Government is also auctioning the mineral blocks associated with the REE.

RAS Exam Relevance

The news is significant for RAS due to its linkage with the policy of mining, security of resources, energy transition, strategic minerals and green energy and economic development of the state. It also illustrates the possibility of cooperation between scientific institutes like IIT Dhanbad with the state agencies for the resource mapping and sustainable mining. The initiative is applicable to the issues of the economy of Rajasthan, mineral resources, industry development, environmental management and circular economy.

Conclusion

The upheaval of extracting the critical minerals from the dumps of the mineral is a great initiative towards sustainable and strategic mining for Rajasthan. The state can benefit the defence, green energy and advanced technology industries as the mineral waste turns into a

RASonly

source for valuable minerals. This innovation will also enhance Indian strategic and economic independence, thereby, ensuring its energy security.

MCQs

MCQ 1:To study the mineral dumps in Rajasthan, who signed an agreement with RSMET?

A. IIT Delhi

B. IIT Dhanbad

C. IIT Bombay

D. IIT Kanpur

Answer: B. IIT Dhanbad

The Rajasthan State Mineral Exploration Trust and IIT Dhanbad have inked a Memorandum of Understanding to research the mineral dumps and search for critical and strategic minerals for commercial production.

MCQ 2: Pink marble and green marble wastes in Rajsthan contained which of the following critical minerals in good amount?

A. Nickel, cobalt, chromium and gallium
B. Gold, silver, copper and tin
C. Coal, limestone, gypsum and mica
D. Iron ore, bauxite, manganese and dolomite

Answer: A. Nickel, cobalt, chromium and gallium

Explanation: As per the preliminary investigations done on pink marble and green marble waste in Rajasthan, quality quantity of Ni, Co, Cr and Ga was found in both the waste.

MCQ 3: Why is it significant to extract critical minerals from mineral dumps?

A. It only increases tourism in mining areas

B. It serves the defence, green energy, aerospace and strategic industries.

C. Replaces all traditional mining without delay.

D. It's only associated with an export promotion of marble.

Answer: B. Provides Defence, Green Energy, Aerospace and Strategic sectors support

Explanation: Critical minerals like nickel, cobalt, chromium and gallium are essential for use in defence, green energy, aerospace and aeronautical sectors, and are thus key to energy, strategic and economic security.

RASonly

राजस्थान खनिज डम्प्स से क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन करेगा

राजस्थान खनन क्षेत्र में एक नवाचारी कदम उठा रहा है, जिसके अंतर्गत खनिज अपशिष्ट डम्प्स से क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर दिए जा रहे विशेष फोकस के अनुरूप राज्य ने खनिज डम्प्स का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया है। राजस्थान में पिंक मार्बल और ग्रीन मार्बल के अपशिष्ट के प्रारंभिक अध्ययन में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की गुणवत्तापूर्ण मात्रा के सकारात्मक संकेत मिले हैं। ये खनिज रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और एयरोनॉटिकल उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकती है।

पहल की प्रमुख विशेषताएं

• राजस्थान अप्रयुक्त खनिज डम्प्स और खनन अपशिष्ट से क्रिटिकल मिनरल्स की खोज कर रहा है।

• पिंक मार्बल और ग्रीन मार्बल के अपशिष्ट में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की उपलब्धता के सकारात्मक संकेत मिले हैं।

• ये खनिज रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस और एयरोनॉटिकल क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं।

• यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से जुड़ी है।

• राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और IIT धनबाद के बीच खनिज डम्प्स के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए समझौता हुआ है।

• इसका उद्देश्य अपशिष्ट से मूल्यवान क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को पुनः प्राप्त कर व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग करना है।

RSMET और IIT धनबाद के बीच समझौता

संस्थागत साझेदारी

खान विभाग ने राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के माध्यम से राजस्थान के खनिज डम्प्स के अध्ययन के लिए IIT धनबाद के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य राज्यभर में मौजूद विशाल और अप्रयुक्त खनिज डम्प्स में उपलब्ध मूल्यवान क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की पहचान करना है।

RASonly

समझौते का उद्देश्य

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य खनिज अपशिष्ट का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना, क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान करना और उनके व्यावसायिक उत्पादन की संभावना तलाशना है। यह पहल सर्कुलर माइनिंग की अवधारणा को बढ़ावा देती है, जिसमें खनन अपशिष्ट को केवल कचरे के रूप में नहीं, बल्कि संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

पायलट प्रोजेक्ट और निष्कर्ष

समझौते के तहत खान विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 78 खनिज डम्प्स की पहचान की गई। इन डम्प्स को 10-10 डम्प्स के क्लस्टर में विभाजित किया गया। उदयपुर जिले और उसके आसपास के एक क्लस्टर में पिंक मार्बल के 8 डम्प्स और ग्रीन मार्बल, जिसे सर्पेन्टिनाइट भी कहा जाता है, के 2 डम्प्स का अध्ययन किया गया।

इन डम्प्स में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की महत्वपूर्ण मात्रा पाई गई। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इनकी सांद्रता पृथ्वी की पपड़ी में इनकी सामान्य उपलब्धता से लगभग 25 से 40 गुना अधिक हो सकती है। यह तथ्य भविष्य की खनिज संसाधन योजना और रणनीतिक खनिज सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आगे का वैज्ञानिक मूल्यांकन

शेष 68 डम्प्स और टेलिंग्स का भी IIT ISM धनबाद के सहयोग से वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा रहा है। इस मूल्यांकन में जियो-रेफरेंस्ड डेटाबेस तैयार करना, मैपिंग, सैंपलिंग, निष्कर्षण, मिनरलॉजिकल विश्लेषण और उपलब्ध संसाधनों का आकलन शामिल है।

इस अध्ययन के माध्यम से टंगस्टन, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता का पता लगाया जाएगा। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, ऋषभदेव, अजमेर, ब्यावर, सावर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, बालेसर, सोजत सिटी और जालौर सहित कई क्षेत्रों में खनिज डम्प्स की पहचान की जा चुकी है।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से संबंध

राष्ट्रीय महत्व

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की खोज और खनन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत रेयर अर्थ मिनरल्स, हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल रेयर मेटल्स पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। राजस्थान की यह पहल मौजूदा खनिज डम्प्स से क्रिटिकल मिनरल्स की खोज कर इस मिशन को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देती है।

RASonly

राजस्थान की भूमिका

राजस्थान ने खनिज डम्प्स से क्रिटिकल मिनरल्स की खोज शुरू कर एक अभिनव पहल की है। राज्य ने रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में भी प्रगति की है। हाल ही में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स के डिपॉजिट्स मिले हैं, जिनसे संबंधित खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है।

RAS परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यह समाचार RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खनन नीति, संसाधन सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, रणनीतिक खनिज, ग्रीन एनर्जी और राजस्थान के आर्थिक विकास से जुड़ा है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि IIT धनबाद जैसे वैज्ञानिक संस्थान राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर संसाधन मैपिंग और सतत खनन में सहयोग कर सकते हैं। यह पहल राजस्थान की अर्थव्यवस्था, खनिज संसाधन, औद्योगिक विकास, पर्यावरण प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे विषयों के लिए उपयोगी है।

निष्कर्ष

राजस्थान द्वारा खनिज डम्प्स से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने की पहल सतत और रणनीतिक खनन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अप्रयुक्त खनिज अपशिष्ट को मूल्यवान खनिजों के स्रोत में बदलकर राज्य रक्षा, ग्रीन एनर्जी और उन्नत तकनीकी उद्योगों को सहयोग दे सकता है। यह नवाचार भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को भी सुदृढ़ करेगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न

MCQ 1: राजस्थान में खनिज डम्प्स के अध्ययन के लिए RSMET ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है?

A. आई आई टी दिल्ली
B. आई आई टी धनबाद
C. आई आई टी बॉम्बे
D. आई आई टी कानपुर

उत्तर : B. आई आई टी धनबाद

व्याख्या : राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और आई आई टी धनबाद के बीच खनिज डम्प्स का अध्ययन करने तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की पहचान करने हेतु समझौता हुआ है।

MCQ 2: राजस्थान में पिंक मार्बल और ग्रीन मार्बल के अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन-से क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण मात्रा में पाए गए हैं?

RASonly

A. निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम

B. सोना, चांदी, तांबा और टिन

C. कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम और अभ्रक

D. लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज और डोलोमाइट

उत्तर: A. निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम

व्याख्या: राजस्थान में पिंक मार्बल और ग्रीन मार्बल के अपशिष्ट के प्रारंभिक अध्ययन में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की गुणवत्तापूर्ण मात्रा के संकेत मिले हैं।

MCQ 3: खनिज डम्प्स से क्रिटिकल मिनरल्स निकालना क्यों महत्वपूर्ण है?

A. यह केवल खनन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाता है

B. यह रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और रणनीतिक क्षेत्रों को सहयोग देता है

C. यह सभी पारंपरिक खनन गतिविधियों को तुरंत समाप्त कर देता है

D. यह केवल मार्बल निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है

उत्तर: B. यह रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और रणनीतिक क्षेत्रों को सहयोग देता है

व्याख्या : निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस और एयरोनॉटिकल क्षेत्रों में उपयोगी हैं। इसलिए ये ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

RASonly

NH-62 Four-Lane Project, Nagaur-Bikaner Connectivity and Western Rajasthan Development, NH-62 Nagaur-Bikaner Four-Lane Project Gets Approval

The National Highway Authority of India (NHAI) of the Union Ministry of Road Transport and Highways has given its approval for the four-laning of the NH-62, Nagaur-Bikaner National Highway. Chief Minister Bhajanlal Sharma approved the project, which is expected to boost the road infrastructure in Rajasthan. The NH-62 Nagaur-Bikaner Four-Lane Project is to be built in BOT (Toll) mode with an estimated cost of around ₹1,359.33 crore. In the western part of Rajasthan, this project is expected to add a new dimension to the development of the area by improving connectivity, and also adding to investments and employment opportunities. It will also aid in the industrial activities along with tourism in Nagaur, Bikaner and surrounding areas.

The NH-62 Four-Lane Project will incorporate the following features:

- The project is related to four-laning of the National Highway-62, Nagaur-Bikaner.
  - It has got approval from the Union Ministry of Road Transport and Highways.
- The estimated cost of the project is approximately ₹1,359.33 crore.
  - The project will be implemented through the BOT (Toll) concept.
  - It will improve the connectivity of the roads in western Rajasthan.
  - It is expected to stimulate investment, jobs, industries and tourism activities.

RAS

Objectives and Benefits

Objectives

- To improve the road infrastructure in the state of Rajasthan.
  - To offer up to date, safe and gliding road connectivity.
- To enhance connectivity between Nagaur and Bikaner and other areas.
- To encourage economic activities in the west of Rajasthan.
  - To help the vision of a developed Rajasthan by augmenting infrastructure.

Benefits

- The project will alleviate travel challenges and enhance transport efficiency.
- Efficient transport infrastructure will be helpful in the attraction of new investments.
- Logistics and economic activity may lead to more job prospects.
- Western Rajasthan will get a boost from industrial and tourism sector.
- It will help in the balanced development of the region by linking key regions more effectively.

Importance of BOT Model

The development of the NH-62 Nagaur-Bikaner project will be done through the BOT (Toll) model. In this model, a private party constructs the project, runs it for a certain number of years, and uses tolls to generate revenue to offset the project's capital costs. Models like these can be used to raise private capital for public works and to ease the upfront cost demands on the public sector.

RAS Exam Relevance

The news is relevant for RAS exam as it is related to Infrastructure Development, Road Connectivity, PPP, Regional Development and economy of Rajasthan. The project also emphasizes the contribution of the national highways to the logistics, the trade, the tourism and the employment. It can be connected to themes like transport, development of western Rajasthan, industrial development, government schemes etc. for road expansion.

Conclusion

Approval of NH-62 Nagaur-Bikaner Four Lane Project is crucial for improving the transport infrastructure in Rajasthan. The investment to this project is approximately ₹1,359.33 crore, which will help in enhancing connectivity in western Rajasthan, promote investment, employment, tourism and industrial activities. It symbolizes the Government's commitment towards building roads and infrastructure in Rajasthan, which are modern, safe and readily available for development.

RASonly

MCQs

MCQ 1: Four lanes construction of the recent National Highway project is approved in Rajasthan, which is?

A. Jaipur-Ajmer NH-48 Project

B. Nagaur-Bikaner NH-62 Project

C. Kota-Jhalawar NH-52 Project

D. Udaipur-Ahmedabad NH-27 Project

Answer: B. Nagaur-Bikaner NH-62 Project

Explanation: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari gave his approval for the four laning of the Nagaur-Bikaner National Highway, NH-62.

MCQ 2:The estimated cost of NH-62 (Nagaur-Bikaner) Four Lane Project is?

A. ₹759.33 crore

B. ₹1,059.33 crore

C. ₹1,359.33 crore

D. ₹2,359.33 crore

Answer: C. ₹1,359.33 crore

Explanation : The Nagaur-Bikaner NH-62 Four Lane Project is being built at an approximate cost of ₹1,359.33 crore.

MCQ 3: What type of model will be used for the NH-62 Nagaur-Bikaner Four-Lane Project?

A. EPC Model
B. BOT (Toll) Model
C. Hybrid Annuity Model
D. Direct Budgetary Support Model

Answer: B. BOT (Toll) Model

Explanation: The project will be implemented in the BOT (Toll) mode, which means that the project will be built and operated by the private developer, and investment will be recovered through toll collection.

RASonly

NH-62 फोरलेन परियोजना, नागौर-बीकानेर कनेक्टिविटी और पश्चिमी राजस्थान का विकास, नागौर-बीकानेर NH-62 फोरलेन परियोजना को मिली मंजूरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-62 के फोरलेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से स्वीकृत यह परियोजना राजस्थान के सड़क आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NH-62 नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना को लगभग ₹1,359.33 करोड़ की लागत से BOT (Toll) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी तथा निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, नागौर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक तथा पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

NH-62 फोरलेन परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

- यह परियोजना नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-62 के फोरलेन निर्माण से संबंधित है।
- परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है।
- परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹1,359.33 करोड़ है।
- इसे BOT (Toll) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
- यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
- इससे निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

- राजस्थान में सड़क आधारभूत संरचना को मजबूत करना।
- आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना।
- नागौर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क को बेहतर बनाना।
- पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

RASonly

• आधारभूत संरचना के विस्तार के माध्यम से विकसित राजस्थान के लक्ष्य को समर्थन देना।

लाभ

• यह परियोजना यात्रा संबंधी कठिनाइयों को कम करेगी और परिवहन दक्षता को बढ़ाएगी।

• बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से नए निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

• लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

• पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों को गति मिलेगी।

• महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावी रूप से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

BOT मॉडल का महत्व

NH-62 नागौर-बीकानेर परियोजना को BOT (Toll) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस मॉडल में निजी संस्था परियोजना का निर्माण करती है, उसे निर्धारित अवधि तक संचालित करती है और टोल संग्रह के माध्यम से अपने निवेश की वसूली करती है। इस प्रकार का मॉडल सार्वजनिक आधारभूत संरचना के विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देता है और सरकार पर तत्काल वित्तीय भार को कम करता है।

RAS परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यह समाचार RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आधारभूत संरचना विकास, सड़क संपर्क, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, क्षेत्रीय विकास और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। यह परियोजना लॉजिस्टिक्स, व्यापार, पर्यटन और रोजगार में राष्ट्रीय राजमार्गों की भूमिका को भी रेखांकित करती है। इसे परिवहन आधारभूत संरचना, पश्चिमी राजस्थान के विकास, औद्योगिक विकास और सड़क विस्तार से जुड़ी सरकारी योजनाओं के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है।

निष्कर्ष

NH-62 नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना की मंजूरी राजस्थान की परिवहन आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग ₹1,359.33 करोड़ के निवेश से यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी तथा निवेश, रोजगार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। यह परियोजना राजस्थान में आधुनिक, सुरक्षित और सुगम सड़क नेटवर्क विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

MCQ 1

राजस्थान में हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के फोरलेन निर्माण को मंजूरी मिली है?

RASonly

A. जयपुर-अजमेर NH-48 परियोजना

B. नागौर-बीकानेर NH-62 परियोजना

C. कोटा-झालावाड़ NH-52 परियोजना

D. उदयपुर-अहमदाबाद NH-27 परियोजना

उत्तर : B. नागौर-बीकानेर NH-62 परियोजना

व्याख्या : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-62 के फोरलेन निर्माण कार्य को मंजूरी दी है।

MCQ 2

NH-62 नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

A. ₹759.33 करोड़

B. ₹1,059.33 करोड़

C. ₹1,359.33 करोड़

D. ₹2,359.33 करोड़

उत्तर: C. ₹1,359.33 करोड़

व्याख्या: नागौर-बीकानेर NH-62 फोरलेन परियोजना को लगभग ₹1,359.33 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा।

MCQ 3

NH-62 नागौर-बीकानेर फोरलेन परियोजना किस मॉडल पर विकसित की जाएगी?

A. EPC मॉडल

B. BOT (Toll) मॉडल

C. Hybrid Annuity मॉडल

D. Direct Budgetary Support मॉडल

उत्तर: B. BOT (Toll) मॉडल

Explanation: इस परियोजना को BOT (Toll) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें निजी डेवलपर परियोजना का निर्माण और संचालन करता है तथा टोल संग्रह के माध्यम से निवेश की वसूली करता है।

RASonly